

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की विदेश नीति—एक विश्लेषण

डॉ सुनीता पालावत,

व्याख्याता – अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा, जिला जयपुर, राजस्थान

शोध सारांश

मनमोहन सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने का जैसा श्रेय दिया जाता है, विदेश नीति के बारे में उनके योगदान को वैसी स्वीकृति नहीं मिली है, जबकि पिछले नौ वर्षों में बतौर प्रधानमंत्री डॉ. सिंह ने भारत की विदेश नीति को बदले वक्त के मुताबिक ढालने और उसे नया स्वरूप देने में खास भूमिका निभाई है। उनकी नीति अपने उद्देश्यों को पाने में कितनी सफल रही, यह अलग बहस का मुद्दा है। मगर ये बहस तभी सार्थक रूप ले सकती है, जब उस विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों को गंभीरता से समझा जाए, जिस पर यूपीए सरकार ने चलने की कोशिश की है।

- मनमोहन सिंह की विदेश नीति को “मनमोहन सिद्धांत” के रूप में जाना जाता था। उनकी नीतियां सिद्धांतों में निहित थीं जैसे
 1. विश्व अर्थव्यवस्था के साथ आर्थिक सहयोग और एकीकरण
 2. शांति और स्थिरता बनाए रखना
 3. सामरिक स्वायत्तता

प्रस्तावना

मनमोहन सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने का जैसा श्रेय दिया जाता है, विदेश नीति के बारे में उनके योगदान को वैसी स्वीकृति नहीं मिली है, जबकि पिछले नौ वर्षों में बतौर प्रधानमंत्री डॉ. सिंह ने भारत की विदेश नीति को बदले वक्त के मुताबिक ढालने और उसे नया स्वरूप देने में खास भूमिका निभाई है। उनकी नीति अपने उद्देश्यों को पाने में कितनी सफल रही, यह अलग बहस का मुद्दा है। मगर ये बहस तभी सार्थक रूप ले सकती है, जब उस विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों को गंभीरता से समझा जाए, जिस पर यूपीए सरकार ने चलने की कोशिश की है।

संसद में जुलाई 1991 में अपने पहले बजट भाषण में, सिंह ने भारत की वैश्विक स्थिति को उसके आर्थिक प्रदर्शन से जोड़ा।

भुगतान संतुलन के तत्काल संकट और राजकोषीय संकट से निपटने के लिए एक रणनीति बनाने के बाद सिंह ने एक व्यापक रणनीतिक सोटिंग में अपनी आर्थिक पहलों को मजबूती से जोड़ा। छह साल बाद एक नए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जनरल 'वर्ल्ड अफेयर्स' के उद्घाटन संस्करण में प्रकाशित एक साक्षात्कार में अपने भाषण को याद करते हुए सिंह ने नरसिंहा राव सरकार द्वारा अनावरण की गई नई आर्थिक नीतियों के विदेश नीति के निहितार्थों को रेखांकित किया। सिंह के मन में कोई संदेह नहीं था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और उसकी आर्थिक नीतियों में नया मोड़ सोवियत

संघ के पतन, 1980 के दशक में चीन और पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं का उदय और भारत का अपना आर्थिक उत्थान के संदर्भ में ली गई एक नई रणनीतिक नीति का हिस्सा था।

हालाँकि यह केवल 1991 के संकट प्रबंधन की बाध्यता नहीं थी जिसने विदेश नीति की प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इस संकट का पूर्व में भी अनुमान लगाया गया था और 1990–91 के संकट से पहले आर्थिक नीति की प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार का एक लंबा इतिहास था। यह पुनर्विचार पूर्व और दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के विकास के अनुभव और चीन के विकास के अनुभव से शुरू हुआ था जिसने अपनी “चार आधुनिकीकरण” नीति, अपनी रणनीतिक नीति और बाहरी दुनिया के साथ अपने संबंधों के सामान्य अभिविन्यास के हिस्से के रूप में, एक दशक पूर्व ही शुरू कर दी थी।

भारत के वित्त मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने से तीन महीने पहले फरवरी 1991 में इस लेखक को दिए गए एक साक्षात्कार में, सिंह ने इकोनॉमिक टाइम्स दिल्ली को बताया कि भारत को पूर्वी एशियाई अनुभव से सीखना होगा और अपनी आर्थिक नीतियों को पुनः उन्मुख करना होगा। उन्होंने भारतीयों को याद दिलाया कि 1960 में, दक्षिण कोरिया और भारत अपने औद्योगिक विकास के स्तर सहित आर्थिक दृष्टि से बराबरी पर थे, लेकिन 1980 के दशक के अंत तक, दक्षिण कोरिया एक नई स्थापित औद्योगिक अर्थव्यवस्था और एशियाई टाइगर बन गया था, जबकि भारत अभी भी पिछड़ रहा है।

फरवरी 1995 में अपने आखिरी बजट भाषण में वे इस सोच पर लौट आए, “एशिया में एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपना सही स्थान लेने वाले पुनरुत्थानशील भारत का यही दृष्टिकोण है, जिसने हमारी आर्थिक नीतियों को प्रेरित किया है।”

भारत की वैश्विक प्रोफाइल और प्रभाव के संबंध में भारत की आर्थिक क्षमताओं के संबंध में सिंह वास्तव में प्रारंभिक नेहरूवादी यथार्थवाद की ओर आकर्षित कर रहे थे जिसे कि बीच के वर्षों के दौरान भुला दिया गया था जब भारतीय विदेश नीति को शीत युद्ध युग की ‘निम्न राजनीति’ और उपरांत उपनिवेशवाद के बाद की ‘उच्च राजनीति’ द्वारा आकार दिया गया था। यह एक समयांतराल था जिसमें “गुटनिरपेक्षता” उस “रणनीति” के बजाय एक “विचारधारा” बन गई थी जो कि प्रारंभ में थी।

भारत के प्रधान मंत्री के रूप में विदेश नीति पर अपने पहले भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, “विदेश नीतियों के बारे में बात करते हुए सदन को याद रखना चाहिए कि ये केवल शतरंज की बिसात पर खाली संघर्ष नहीं हैं। उनके पीछे हर तरह की बातें हैं। अंततः विदेश नीति आर्थिक नीतियों का परिणाम है और जब तक भारत ठीक से विकसित नहीं हो जाता इसकी आर्थिक नीति या विदेश नीति बल्कि अस्पष्ट होगी, बल्कि अपरिपक्व होगी और यह कहना कि हम शांति और स्वतंत्रता के लिए खड़े हैं, इसकी कमजोरी के परिणामस्वरूप, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होगा, क्योंकि हर देश एक ही बात कहने के लिए तैयार है, चाहे उसका मतलब हो या न हो। फिर हम किसके लिए खड़े हैं? वैसे आपको इस तर्क को आर्थिक क्षेत्र में विकसित करना होगा। जैसा कि आज है, इस तथ्य के बावजूद कि हम एक सरकार के रूप में कुछ समय के लिए सत्ता में रहे हैं, मुझे खेद है कि हमने अभी तक कोई रचनात्मक आर्थिक योजना या आर्थिक नीति नहीं बनाई है 33 जब हम ऐसा करते हैं, तो यह इस सदन के सभी भाषणों से अधिक हमारी विदेश नीति को अधिक संचालित करेगा।”

सिंह की पहली विदेश यात्रा बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (बिम्सटेक) शिखर

सम्मेलन के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के लिए बैंकॉक थी, उनकी पहली महत्वपूर्ण बैठक संयुक्त राष्ट्र जनरल के मौके पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के साथ सितंबर 2004 में हुई थी। कच्चे तेल की बढ़ती कीमत दोनों के दिमाग में थी इसलिए बातचीत स्वाभाविक रूप से विषय पर केंद्रित थी। सिंह ने बुश से कहा कि आयातित तेल पर भारत की निर्भरता बढ़ गई है और यदि भारत को दीर्घकाल में उच्च विकास बनाए रखना है तो उसके पास वैकल्पिक ऊर्जा विकल्पों का पता लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। असैन्य परमाणु ऊर्जा का विस्तार करने की भारत की इच्छा एक भेदभावपूर्ण वैश्विक शासन द्वारा बाधित थी। बुश ने समस्या को जल्दी समझ लिया। बुश ने सहमति व्यक्त की कि यदि चीन और भारत विकास की उच्च दर से वृद्धि जारी रखते हैं तो उनकी प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत बढ़ेगी। यदि विश्व समुदाय को यह सुनिश्चित करना है कि इसका परिणाम तेल की कीमतों में तेज वृद्धि नहीं है, जो निश्चित रूप से अमेरिकी उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाएगा, तो भारत के पास परमाणु ऊर्जा विकल्प का पता लगाने की क्षमता होनी चाहिए। बुश ने तुरंत इस तर्क को स्वीकार कर लिया और आशा व्यक्त की कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत भारत को परमाणु ऊर्जा विकल्प का प्रयोग करने में मदद करने के लिए मिलकर काम करने में सक्षम होंगे। इसी तरह असैनिक परमाणु ऊर्जा का मुद्दा सबसे पहले उठा। मई 2005 की शुरुआत में मास्को में उनकी अगली बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और भारत को अपनी विकास प्रक्रिया को बनाए रखने में मदद करने पर बातचीत को आगे बढ़ाया गया। 18 जुलाई 2005, असैन्य परमाणु ऊर्जा का मुद्दा भारत के आर्थिक और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समान रूप से महत्वपूर्ण पहलों में से एक था।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय पहल के रूप में जो शुरू हुआ, वह

तेल की बढ़ती कीमतों के साथ उनकी साझा चिंता और परमाणु और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने में उनकी साझा रुचि को दर्शाता है, जो भारत के लिए एक प्रमुख वैश्विक राजनयिक पहल के रूप में विकसित हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझौता भारत द्वारा 145 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) और 45 सदस्यीय एनएसजी के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने पर निर्भर था। जिन समझौतों पर अब पांच और छैल और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस और रूस के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं, वे भारत की असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षमता के विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये समझौते, एक ‘पृथक्करण योजना’ पर आधारित हैं जो नागरिक ऊर्जा कार्यक्रम से भारत के सैन्य परमाणु कार्यक्रम को फायरवॉल करता है, यह भारत को परमाणु हथियार शक्ति के रूप में एक वास्तविक मान्यता भी देता है। सिंह ने मुख्य रूप से अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाकर और उच्च प्रौद्योगिकी में व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करके भारत के विकास विकल्पों को व्यापक बनाने के उद्देश्य से इस पहल को आगे बढ़ाया। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु सहयोग समझौते के अन्य रणनीतिक और राजनीतिक आयाम हो सकते हैं, यह मुख्य रूप से भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए सिंह की चिंता से प्रेरित था। इस समझौते के लिए तात्कालिकता की भावना। भारतीय राजनीतिक ‘वाम’ और ‘दक्षिणपंथ’ पर समझौते के विशुद्ध रूप से ‘वैचारिक’ आलोचकों ने समझौते के आर्थिक महत्व के लिए सिंह के समान वजन देने से इनकार कर दिया। वामपंथियों ने खारिज कर दिया इस आधार पर समझौता कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घनिष्ठ सामरिक संबंधों और इस आधार पर दक्षिणपंथी होगा कि यह भारत की सामरिक स्वायत्ता पर अतिक्रमण करेगा। सिंह ने समझौते को भारत की परमाणु

ऊर्जा क्षमता, समग्र ऊर्जा सुरक्षा के विस्तार के लिए आवश्यक माना। और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग के लिए नए रास्ते खोलना, भारत की विकास क्षमता में योगदान देना।

सिंह ने कृषि और ज्ञान संबंधी पहलों को भी समान रूप से महत्वपूर्ण माना। उन्होंने अक्सर भारत की 'पहली' हरित क्रांति में संयुक्त राज्य की सहायता की सहायक भूमिका पर जोर दिया है और 'दूसरी हरित क्रांति' शुरू करने में इस तरह के सहयोग की संभावना को रेखांकित किया है। इसी संदर्भ में उन्होंने कृषि अनुसंधान और विकास में संयुक्त राज्य अमेरिका के निवेश की मांग की। इसी तरह उन्होंने भारत की ज्ञान अर्थव्यवस्था के और विकास में संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन मांगा। इसलिए, संयुक्त बयान का पूरा ध्यान विकासोन्मुख प्राथमिकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर था। 17 अगस्त 2006 को संसद में असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर प्रधान मंत्री का बयान इस विषय पर उनके द्वारा दिया गया सबसे व्यापक बयान था। जबकि बयान का दूसरा भाग अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया था, पहले कुछ पैरा बिना बोले बोले गए थे। सिंह ने केवल ऊर्जा सुरक्षा के आधार पर परमाणु समझौते का बचाव किया और यहां तक कि साहसपूर्वक यह भी कहा कि भारत का परमाणु कार्यक्रम वास्तव में एक नागरिक ऊर्जा कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ था, न कि एक सैन्य हथियार कार्यक्रम के रूप में। जवाहरलाल नेहरू के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद में ऐसा कहने का साहस नहीं किया। सिंह ने कहा, 'सर, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि बड़े पैमाने पर गरीबी तभी दूर की जा सकती है जब हमारे पास तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो ... यदि भारत को 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की दर से विकास करना है और शायद, भारत को बढ़ती मात्रा की आवश्यकता है ऊर्जा... इस संदर्भ में, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए प्राथमिक प्रेरणा ऊर्जा का उत्पादन था, रक्षा बहुत

बाद में आई... मानव विकल्पों को व्यापक बनाने के बारे में सभी विकास। और, जब ऊर्जा सुरक्षा की बात आती है, तो हमारे विकल्पों का अर्थ है कि हमें परमाणु ऊर्जा का प्रभावी उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। यदि आवश्यकता पड़ी, यदि आर्थिक गणना की मांग है कि यह सबसे अधिक लागत प्रभावी साधन है।

भारत की सभी प्रमुख शक्तियों के साथ जुड़ाव व्यापार, निवेश और कुशल लोगों की आवाजाही पर केंद्रित है। जबकि आतंकवाद और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता जैसे राजनीतिक मुद्दों पर शिखर-स्तरीय बैठकों में चर्चा होती है, और संयुक्त बयानों में परिलक्षित होती है, सभी प्रमुख द्विपक्षीय संबंधों की कुंजी आर्थिक जुड़ाव की सीमा, सीमा और गहराई है। यहां तक कि कठिन भारत-चीन संबंध भी द्विपक्षीय व्यापार में तेजी से वृद्धि के साथ कायम रहे हैं, सीमा पर चर्चा एक खांचे में फंस गई है। विकसित दुनिया, विशेष रूप से जी-8 के लिए सिंह के दृष्टिकोण को हेलिजेंडम शिखर सम्मेलन के बाद मीडिया में उनकी टिप्पणी में अभिव्यक्त किया गया था कि जी-5 विकासशील देश जी-8 के साथ बैठक में भाग लेने के लिए खुश थे, जब तक उनके पास न केवल मूक पर्यवेक्षक के रूप में बल्कि वैश्विक मुद्दों पर जी-8 के भीतर सोच को आकार देने का अवसर। सिंह ने जापान में छठे शिखर सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया, जब पहली बार यह संकेत दिया गया कि मेजबानों ने G-8 और G-5 नेताओं के बीच केवल एक घंटे की बातचीत की व्यवस्था की थी, और वह भी नाश्ते पर। सिंह ने अपने स्टैंड के लिए G-5 समर्थन हासिल किया कि तथाकथित "आउटरीच मीटिंग" का कोई मतलब नहीं है जब तक कि G-5 चिंताओं को छठे-8 के बयान में शामिल नहीं किया जाता। G-8 और G-5 के बीच G-8 के संयुक्त बयान का मसौदा तैयार करने और उसे अपनाने के बजाय 'पहले' के बीच यह आवश्यक बातचीत थी।

विदेश नीति

- मनमोहन सिंह की विदेश नीति को “मनमोहन सिद्धांत” के रूप में जाना जाता था। उनकी नीतियां सिद्धांतों में निहित थीं जैसे-
 1. विश्व अर्थव्यवस्था के साथ आर्थिक सहयोग और एकीकरण
 2. शांति और स्थिरता बनाए रखना
 3. सामरिक स्वायत्तता
- अहिंसा और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों का पालन करते हुए, उन्होंने अधिकांश पड़ोसी देशों और वैश्विक शक्तियों के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखे। भारत की विकासात्मक प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखा गया।

यूएसए के साथ संबंध

- मनमोहन सिंह ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2005 में, उन्होंने भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते या 123 समझौते की शुरुआत की। जॉर्ज बुश के साथ चर्चा 2005 में रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर के रूप में समाप्त हुई। भारत को परमाणु ईधन और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्राप्त हुई, जबकि भारत अपनी सैन्य और परमाणु सुविधाओं को अलग करने और अपने परमाणु रिएक्टरों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की देखरेख में रखने पर सहमत हुआ।).
- भारत और अमेरिका के बीच इस वाटरशेड सौदे ने अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर किए बिना भारत को “वास्तविक” स्थिति से सम्मानित किया। IAEA द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद 1 अगस्त, 2008 को वाटरशेड सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- हालाँकि, भारत-अमेरिका परमाणु समझौते को भारत में विपक्षी दलों और राजनीतिक

कार्यकर्ताओं की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। कड़े विरोध के बीच मनमोहन सिंह की सरकार मामूली पैमाने पर विश्वास मत हासिल करने से बच गई।

चीन के साथ संबंध

• मनमोहन सिंह के कार्यकाल में चीन के साथ संबंध प्रगाढ़ हुए। भारत चीन के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक बन गया और 2007 में 36 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। सिक्किम में नाथुला दर्दा, 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद से कूटनीतिक रूप से बंद था, मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान लगभग चार दशकों के बाद फिर से खुल गया। चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ की यात्रा के बाद द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण विकास शुरू हुए। उनकी “दस-आयामी रणनीतियों” में शामिल हैं।

1. द्विपक्षीय संबंधों का व्यापक विकास
 2. संस्थागत संबंधों और संवाद तंत्र को मजबूत करना
 3. वाणिज्यिक और आर्थिक आदान-प्रदान को समेकित करना
 4. परस्पर लाभकारी सहयोग का विस्तार
 5. रक्षा सहयोग के माध्यम से आपसी विश्वास और भरोसे का विकास
 6. बकाया मुद्दों का शीघ्र निपटान
 7. सीमा पार कनेक्टिविटी और सहयोग को सुगम बनाना
 8. विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देना
 9. सांस्कृतिक संबंधों और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान को मजबूत करना
 10. क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर सहयोग बढ़ाना।
- भारत और चीन के बीच तीन सिस्टर-सिटी साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए। वह थेरें

दिल्ली—बीजिंग, कोलकाता—कुनमिंग, और बैंगलोर—चेंगदू

पाकिस्तान के साथ संबंध

- सिंह ने पाकिस्तान के साथ संबंधों में वाजपेयी की नीति को जारी रखा। भले ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 2005 में भारत का दौरा किया, लेकिन दोनों के बीच शांति स्थापित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ। 7 अप्रैल 2005 को, मनमोहन सिंह ने नियंत्रण रेखा के पार श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच पहली बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। हालाँकि, मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण और व्यावहारिक संबंध बनाए रखा। 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया।

जापान के साथ संबंध

- 2006 में, मनमोहन सिंह ने अपनी जापान यात्रा के बाद 'भारत—जापान रणनीतिक और वैशिक साझेदारी' पर हस्ताक्षर किए। भारत के सुजुकी सहित जापानी ऑटोमोबाइल निर्माताओं के साथ घनिष्ठ संबंध थे, जिसके कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में बड़ा निवेश और सहयोग हुआ। जापान ने 2007 में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ हिंद महासागर में "मालाबार" अभ्यास शुरू किया। भारत और जापान ने आतंकवाद से लड़ने के लिए एक सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा, जापान ने दिल्ली और मुंबई के बीच हाई-स्पीड रेल के निर्माण के लिए 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कम ब्याज वाले ऋण की पेशकश की।

इजराइल के साथ संबंध

- मनमोहन सिंह ने अपने पूरे कार्यकाल में इजराइल के साथ मधुर संबंध बनाए रखे। दोनों देशों ने निवेश के माध्यम से संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति की है।
- यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस सहित यूरोपीय देशों के साथ संबंध भी स्थिर थे। उनके कार्यकाल में ब्राजील और अफ्रीकी देशों से भी संबंध सुधरे। नई दिल्ली द्वारा आयोजित 2006 के भारत—अफ्रीकी शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी देशों के नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने ईरान—पाकिस्तान—भारत पाइपलाइन पर बातचीत के साथ—साथ ईरान के साथ संबंध भी बनाए रखे।
- भारत के सहयोगियों में से एक, रूस के साथ संबंध वास्तव में सहज थे, भारत को हथियारों की देरी पर कुछ संघर्षों के अलावा।

अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण प्रयासों की सफलता और एक उदारवादी, बहुलवादी और लोकतांत्रिक समाज के रूप में इसके उद्भव को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपने सभी संसाधनों को पूल करना चाहिए ... हम पाकिस्तान में लोकतंत्र की वापसी का स्वागत करते हैं। हम भारत के बीच सभी लंबित मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और पाकिस्तान, जम्मू और कश्मीर के मुद्दे सहित, शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से। हम नेपाल और भूटान में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों के सत्ता में आने का भी स्वागत करते हैं।"

लोकतंत्र के बारे में औपचारिक बयानों से परे जाना और इसे विशुद्ध रूप से देखने से दूर रहना रणनीतिक दृष्टि से, सिंह का लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था की अभिव्यक्ति थी। एक राजनेता के रूप में लोकतंत्र के महत्व को रेखांकित किया तथा अतिवाद, कट्टरवाद और आतंकवाद से

निपटने के रूप में लोकतंत्र को एक सक्षम संस्था माना, विशेष रूप से एशिया के संदर्भ में। लोकतंत्र ही “बेजुबानों को आवाज” देने और “अशक्ति को शक्ति” देने की क्षमता रखता है। सरकारों को “गोलियों के बजाय मतपत्रों के माध्यम से” बदलना जिसे सिंह ने अपने ‘महान मूल्यों के रूप में देखा और इस बात पर जोर दिया कि असहिष्णुता और आतंकवाद से निपटने वाली दुनिया में लोकतंत्र ही एकमात्र विकल्प है। भारत और शेष लोकतांत्रिक विश्व को आर्थिक के बजाय लोकतंत्र के लिए एक सामाजिक और राजनीतिक वकालत करनी चाहिए और आर्थिक विकास की आड़ में लोकतंत्र की आलोचना करने के अभ्यर्तों को जवाब लोकतंत्र की तरफदारी से देना चाहिए। विकासशील दुनिया में एक ‘गैर-लोकतांत्रिक’ संस्था के भीतर चीन के उदय ने लोकतंत्र के गुणों और दोषों के बारे में पुरानी बहस को पुनर्जीवित कर दिया था। जबकि गैर-लोकतांत्रिक शासन उच्च विकास को बढ़ावा देने में सक्षम हो सकते हैं, परंतु वे मानवीय भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक राजनीतिक स्थान की पेशकश नहीं करते हैं, विशेष रूप से मूल मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति के संदर्भ में तथा जटिल बहु-जातीय, बहु-सांस्कृतिक, बहु-भाषी, बहु-धार्मिक और अक्सर बहु-राष्ट्रीय देशों के संदर्भ में पूर्ण स्वतंत्र वातावरण प्रदान नहीं करते। यह भी तर्क दिया जा सकता है कि सिंह भारत के लिए उदारवाद के रणनीतिक महत्व का व्यावहारिक दृष्टिकोण भी रख रहे थे। आखिरकार, भारत की सामरिक संपत्तियों में से एक उसकी ‘ज्ञान अर्थव्यवस्था’ है। एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में भारतीय डायरेसोर का मूल्य केवल पूँजी प्रवाह के बारे में नहीं था बल्कि इसके ‘ब्रेन बैंक’ होने के बारे में भी था, जैसा कि सिंह ने कई अवसरों पर कहा भी था।

सिंह के महत्वपूर्ण और बार-बार दोहराए जाने वाले बयानों में से एक 1943 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विंस्टन चर्चिल के भाषण का

उद्धरण है, जब उन्होंने कहा था, “भविष्य के साम्राज्य मन के साम्राज्य होंगे।”

सिंह ने भारत में निवेश शिक्षा, कौशल, क्षमता और क्षमता निर्माण के रणनीतिक महत्व पर जोर देते हुए बार-बार इसका उल्लेख किया है। यहां तक कि भारत-यूनाइटेड सामरिक संबंधों में भी सिंह ने इसे बहुत महत्व दिया। द इंडिया-यूनाइटेड स्टेट्स नॉलेज इनिशिएटिव, फुलब्राइट-नेहरु फैलोशिप की शुरुआत, कृषि अनुसंधान की पहल और इसी तरह के सभी भारत के विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के ज्ञान और प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा थे। यहां तक कि भारत-संयुक्त राज्य असैन्य परमाणु समझौते को उच्च तकनीकी क्षेत्रों में ज्ञान प्रवाह की बाधाओं को दूर करने के साधन के रूप में देखा जाना चाहिए।

मनमोहन सिंह सिद्धांत को चुनौती

यह स्पष्ट होना चाहिए कि मनमोहन सिंह सिद्धांत समय की उपज थी। यह अधिक अर्थव्यवस्था के खुलेपन के युग में भारत के आर्थिक पुनरुत्थान की अभिव्यक्ति थी। भारत के लिए उच्च विकास की तात्कालिक गति को बनाए रखना महत्वपूर्ण था।

यह सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ा गया कि यह सामाजिक रूप से अधिक समावेशी और क्षेत्रीय रूप से अधिक संतुलित नीति को अपनाया जाये तथा साथ ही यह भी लगातार सुनिश्चित किया जाए कि घरेलू आर्थिक और राजनीतिक वातावरण को जारी रखने के लिए भी यह अनुकूल हो। मनमोहन सिंह के सिद्धांत को तात्कालिक परिस्थितियों को चुनौतीपूर्ण समझाते हुए लागू करना ही सबसे बड़ा सवाल था।

भारत के राजदूतोंधुच्चायुक्तों के नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अपनी

विदेश नीति की सूत्रवार व्याख्या की और कहा कि हमारी विदेश नीति पांच सिद्धांतों से परिभाषित हुई है। पहला, दुनिया से भारत के रिश्ते देश की विकास संबंधी प्राथमिकताओं से तय हुए हैं। मकसद है देश की भलाई के अनुकूल वैश्विक वातावरण बनाना। बाकी चार पहलू हैं— विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अधिक एकीकरण, सभी बड़ी ताकतों के साथ संबंधों में अधिक स्थिरता, भारतीय उपमहाद्वीप में अधिक क्षेत्रीय सहयोग एवं संपर्क और पांचवां यह कि विदेश नीति सिर्फ स्वार्थ से तय नहीं होती, बल्कि यह भारतीय जन को अतिप्रिय उसूलों पर आधारित है।

पांचवें बिंदु की व्याख्या करते हुए डॉ. सिंह ने कहा, 'बहुलतावादी, धर्मनिरपेक्ष, उदार लोकतंत्र के ढांचे में आर्थिक विकास की तलाश के भारत के प्रयोग ने दुनिया भर में लोगों को प्रेरित किया है।' यानी अपनी विदेश नीति को उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से उपजे मूल्यों की परंपरा से संचालित बताया। किसी विचारधारा को विदेश नीति के इन सिद्धांतों पर शायद ही कोई बुनियादी एतराज हो।

मगर इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में यूपीए सरकार कितनी सफल रही, इस पर जरूर अलग-अलग राय उभर सकती है। खासकर क्षेत्रीय सहयोग के मुद्दे पर। यूपीए सरकार ने पाकिस्तान और चीन से संबंधों को सुधारने में जितने जोखिम उठाए, उसी अनुपात में उसके सकारात्मक परिणाम मिले, यह कहना कठिन है। बहरहाल, प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम दिनों में विदेश नीति की जो वैचारिक व्याख्या प्रस्तुत की है, वह भविष्य की सरकारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक दस्तावेज बनी रहेगी।

लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और मनमोहन सिंह सिद्धांत

मनमोहन सिंह सिद्धांत को परिभाषित करने वाला एक महत्वपूर्ण विचार जिस पर राजा मोहन ने ध्यान आकर्षित किया, वह 2005 की शुरुआत में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में सिंह की टिप्पणियों में कहा गया था, "यदि कोई "भारत का विचार" है जिसके द्वारा भारत को परिभाषित किया जाना चाहिए, तो यह एक समावेशी, खुले, बहु-सांस्कृतिक, बहु-जातीय, बहु-भाषी समाज का विचार है। मेरा मानना है कि 21वीं सदी में राजनीति की यह प्रमुख प्रवृत्ति है कि सभी समाजों का विकास होना चाहिए। इसलिए, हम इतिहास और हम मानव जाति के प्रति जिम्मेदारी दिखायें और यह दर्शायें कि बहुलतावाद काम करता है। भारत को यह दिखाना चाहिए कि लोकतंत्र विकास प्रदान कर सकता है और हाशिए पर रहे रहे लोगों को सशक्त बना सकता है। उदार लोकतंत्र आज की दुनिया में राजनीतिक संगठन के स्वाभाविक विकास का क्रम है। सभी वैकल्पिक प्रणालियाँ, अलग-अलग डिग्री में सत्तावादी और बहुसंख्यकों के प्रति प्रतिबद्ध हैं जो कि विकास के दृष्टिकोण से एक विपथन हैं। जिस तरह विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं ने "संक्रमण में अर्थव्यवस्थाओं" को खुली अर्थव्यवस्थाओं में विकसित करने में सक्षम बनाया, विकसित लोकतंत्रों को भी "संक्रमण में समाज" को खुले समाज बनने में सहायता करनी चाहिए। मेरा मानना है कि दुनिया के प्रति भारत की नीतियां हमारी राष्ट्रीयता के मूल मूल्यों के प्रति इस प्रतिबद्धता से आकार लेना चाहिए। हमें दुनिया भर में उदार लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की रक्षा करने वालों के साथ अपनी पहचान बनाने पर गर्व होना चाहिए।"

यह वह विचार है जो सितंबर 2 में संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य लोकतंत्रों के साथ संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र को सह-लॉन्च करने के भारत के फैसले को रेखांकित करता है। सिंह ने विकासशील दुनिया में लोकतंत्र विकास के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रतिबद्धता

से प्रेरणा ली। और सामरिक हिस्सेदारी के लिए एशिया, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के निर्माण को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की भारत की निरंतर नीति को ध्यान में रखते हुए “लोकतंत्र के निर्यात” की वकालत नहीं की। लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से साहसपूर्वक यह कहने में संकोच नहीं किया कि लोकतंत्र भारत के लिए अच्छा है और पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। निश्चित रूप से यह तर्क दिया जा सकता है कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र निर्माण में भारत की विशेष रुचि थी और सिंह यह स्वीकार करने से नहीं हिचकिचाए। उन्होंने लोकतंत्र को राजनीति में संयम को बढ़ावा देने और उग्रवाद, कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक प्रभावी साधन के रूप में देखा। भारत ने इन आधारों पर अफगानिस्तान में हामिद करजई की सरकार के लिए अपने समर्थन को उचित ठहराया, और नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र का खुला समर्थन किया। केवल म्यांमार के मामले में ही म्यांमार की एकता, अखंडता और स्थिरता के बारे में चिंताओं सहित विभिन्न रणनीतिक कारणों से सार्वजनिक घोषणा करने में मितव्ययिता रही है। डॉ सिंह ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के निर्माण के बढ़ते ज्वार के साथ भारत की संतुष्टि को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया।

लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और मनमोहन सिंह सिद्धांत

मनमोहन सिंह सिद्धांत को परिभाषित करने वाला एक महत्वपूर्ण विचार जिस पर राजा मोहन ने ध्यान आकर्षित किया, वह 2005 की शुरुआत में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में सिंह की टिप्पणियों में कहा गया था, “यदि कोई ‘भारत का विचार’ है जिसके द्वारा भारत को परिभाषित किया जाना चाहिए, तो यह एक समावेशी, खुले, बहु-सांस्कृ

तिक, बहु-जातीय, बहु-भाषी समाज का विचार है। मेरा मानना है कि 21वीं सदी में राजनीति की यह प्रमुख प्रवृत्ति है कि सभी समाजों का विकास होना चाहिए। इसलिए, हम इतिहास और हम मानव जाति के प्रति जिम्मेदारी दिखायें और यह दर्शायें कि बहुलतावाद काम करता है। भारत को यह दिखाना चाहिए कि लोकतंत्र विकास प्रदान कर सकता है और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बना सकता है। उदार लोकतंत्र आज की दुनिया में राजनीतिक संगठन के स्वाभाविक विकास का क्रम है। सभी वैकल्पिक प्रणालियाँ, अलग-अलग डिग्री में सत्तावादी और बहुसंख्यकों के प्रति प्रतिबद्ध हैं जो कि विकास के दृष्टिकोण से एक विपथन हैं। जिस तरह विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं ने “संक्रमण में अर्थव्यवस्थाओं” को खुली अर्थव्यवस्थाओं में विकसित करने में सक्षम बनाया, विकसित लोकतंत्रों को भी “संक्रमण में समाज” को खुले समाज बनने में सहायता करनी चाहिए। मेरा मानना है कि दुनिया के प्रति भारत की नीतियां हमारी राष्ट्रीयता के मूल मूल्यों के प्रति इस प्रतिबद्धता से आकार लेना चाहिए। हमें दुनिया भर में उदार लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की रक्षा करने वालों के साथ अपनी पहचान बनाने पर गर्व होना चाहिए।”

यह वह विचार है जो सितंबर 2 में संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य लोकतंत्रों के साथ संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र को सह-लॉन्च करने के भारत के फैसले को रेखांकित करता है। सिंह ने विकासशील दुनिया में लोकतंत्र विकास के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रतिबद्धता से प्रेरणा ली। और सामरिक हिस्सेदारी के लिए एशिया, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के निर्माण को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की भारत की निरंतर नीति को ध्यान में रखते हुए “लोकतंत्र के निर्यात” की वकालत नहीं की। लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से साहसपूर्वक

यह कहने में संकोच नहीं किया कि लोकतंत्र भारत के लिए अच्छा है और पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। निश्चित रूप से यह तर्क दिया जा सकता है कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र निर्माण में भारत की विशेष रुचि थी और सिंह यह स्वीकार करने से नहीं हिचकिचाए। उन्होंने लोकतंत्र को राजनीति में संयम को बढ़ावा देने और उग्रवाद, कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक प्रभावी साधन के रूप में देखा। भारत ने इन आधारों पर अफगानिस्तान में हामिद करजई की सरकार के लिए अपने समर्थन को उचित ठहराया, और नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र का खुला समर्थन किया। केवल म्यांमार के मामले में ही म्यांमार की एकता, अखंडता और स्थिरता के बारे में चिंताओं सहित विभिन्न रणनीतिक कारणों से सार्वजनिक घोषणा करने में मितव्ययिता रही है। डॉ सिंह ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के निर्माण के बढ़ते ज्वार के साथ भारत की संतुष्टि को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया।

कहा,

"मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत में हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए गहराई से और ईमानदारी से प्रतिबद्ध हैं क्योंकि हम सभी एक ही वैश्विक पर्यावरण को साझा करते हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राचीन हिंदू कहावत - वसुधैव कुटुंबकम - 'संपूर्ण ब्रह्मांड' से निकला है। जैसा कि मैंने कुछ महीने पहले जर्मनी में ३४ शिखर सम्मेलन में कहा था, भारत अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है। हम इस दायित्व को स्वीकार करने को तैयार हैं कि हमारा व्यक्ति उत्सर्जन कभी भी विकसित देशों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन से अधिक नहीं होगा। यदि विकसित देश अपने प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को कम करने में सफल होते हैं, तो यह दबाव बढ़ाएगा और हम सभी के लिए भी प्रोत्साहन का स्रोत होगा। चाहे

वह व्यापार नीति पर हो या जलवायु परिवर्तन पर, या वास्तव में किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय दायित्व पर, भारत ने हमेशा वैश्विक समुदाय के साथ काम किया है। इसके अलावा, भारत कभी भी अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से पीछे नहीं हटा है। भारत एक विश्वसनीय भागीदार, एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक रहा है। भारत अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कानून के शासन का सम्मान करता है।"

यह विचार कि भारत एक "अनुमानित भागीदार", एक "सामान्य देश", एक जिम्मेदार, भरोसेमंद भरोसेमंद देश है, सिंह की सोच और उनके विचारों का एक महत्वपूर्ण विषय था, क्योंकि उनका मानना था कि भारत के नेता स्वतंत्रता के समय से अपने देश को देखते थे। एक मुहावरा कि "एक खुला समाज और एक खुली अर्थव्यवस्था" का सिंह द्वारा बार-बार इस्तेमाल किया गया था, इस तथ्य को भी रेखांकित करता है कि भारत एक खुली किताब है। और भारत एक पारदर्शी, अनुमानित और भरोसेमंद देश है।

यही कारण है कि भारत ने विश्व व्यापार संगठन में शामिल होना चुना। भारत गैट का संस्थापक सदस्य है। आप इस तथ्य को स्वीकार करेंगे कि हमने उरुग्वे दौर की अपनी सभी प्रतिबद्धताओं का पालन किया। वास्तव में, हमारी फर्मों को इन प्रतिबद्धताओं से लाभ हुआ। जबकि हम इन दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, हमें उन तरीकों का भी पता लगाना चाहिए जिनमें विकासशील देश आधुनिकीकरण की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। हमने बौद्धिक अधिकार संपदा की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। लेकिन, वैश्विक अर्थव्यवस्था, ज्ञान सृजन का पूर्ण निजीकरण, वैश्विक समुदाय इसे वहन नहीं कर सकता विशेष रूप से क्षेत्रों में अनुसंधान और दबावों के क्षेत्र में। हमें बौद्धिक संपदा की रक्षा करने वाले तंत्र विकसित करने

की जरूरत है और साथ ही, ऐसे तंत्र की जो गरीबों की जरूरतों को पूरा करें। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास का निजीकरण, आधुनिक समाजों को ज्ञान साझा करने के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है जहां इस तरह का ज्ञान सभी मानव जाति के लिए लाभकारी है।"

इसी तरह, हेलिंगेडम में, उन्होंने जलवायु परिवर्तन वार्ताओं पर भारत के रुख को यह कहते हुए परिभाषित किया कि भारत इसे सीमित करेगा। इसका प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा व्यवहार में परिभाषित स्तरों तक है। जैसा कि सिंह ने कहा, "जब हम जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पारिस्थितिक गिरावट और पर्यावरण नीतियों की समस्या पर विचार करते हैं, तो इसी तरह के व्यापार को निरुत्साहित करने की आवश्यकता होती है। विकासशील दुनिया निकट भविष्य में व्ल उत्सर्जन की प्रति व्यक्ति खपत को बढ़ती देखना जारी रखेगी। यह वैश्विक संसाधनों पर दबाव डालेगा। बड़ा सवाल यह है कि विकास प्रक्रिया की स्थिरता के बारे में हमारी साझा चिंता के खिलाफ हम दुनिया के गरीब देशों की आकांक्षाओं को कैसे संतुलित करते हैं?

यही कारण है कि भारत ने विश्व व्यापार संगठन में शामिल होना चुना। भारत गैट का संरक्षणक सदस्य है। आप इस तथ्य को स्वीकार करेंगे कि हमने उरुग्वे दौर की अपनी सभी प्रतिबद्धताओं का पालन किया। वास्तव में, हमारी फर्मों को इन प्रतिबद्धताओं से लाभ हुआ। जबकि हम इन दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, हमें उन तरीकों का भी पता लगाना चाहिए जिनमें विकासशील देश आधुनिकीकरण की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। हमने बौद्धिक अधिकार संपदा की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। लेकिन, वैश्विक अर्थव्यवस्था, ज्ञान सृजन का पूर्ण निजीकरण, वैश्विक समुदाय इसे

वहन नहीं कर सकता विशेष रूप से क्षेत्रों में अनुसंधान और दवाओं के क्षेत्र में। हमें बौद्धिक संपदा की रक्षा करने वाले तंत्र विकसित करने की जरूरत है और साथ ही, ऐसे तंत्र की जो गरीबों की जरूरतों को पूरा करें। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास का निजीकरण, आधुनिक समाजों को ज्ञान साझा करने के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है जहां इस तरह का ज्ञान सभी मानव जाति के लिए लाभकारी है।"

इसी तरह, हेलिंगेडम में, उन्होंने जलवायु परिवर्तन वार्ताओं पर भारत के रुख को यह कहते हुए परिभाषित किया कि भारत इसे सीमित करेगा। इसका प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा व्यवहार में परिभाषित स्तरों तक है। जैसा कि सिंह ने कहा, "जब हम जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पारिस्थितिक गिरावट और पर्यावरण नीतियों की समस्या पर विचार करते हैं, तो इसी तरह के व्यापार को निरुत्साहित करने की आवश्यकता होती है। विकासशील दुनिया निकट भविष्य में व्ल उत्सर्जन की प्रति व्यक्ति खपत को बढ़ती देखना जारी रखेगी। यह वैश्विक संसाधनों पर दबाव डालेगा। बड़ा सवाल यह है कि विकास प्रक्रिया की स्थिरता के बारे में हमारी साझा चिंता के खिलाफ हम दुनिया के गरीब देशों की आकांक्षाओं को कैसे संतुलित करते हैं?

वर्ष 2006–08 के दो प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर, अर्थात् बहुपक्षीय व्यापार वार्ता, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा और वैश्विक ऊर्जा, खाद्य और वित्तीय संकट के प्रबंधन पर, सिंह ने बार-बार भारत की आवाज सुनने की आवश्यकता की बात की, लेकिन, प्रतिबद्ध भारत, वैश्विक मुद्दों के प्रबंधन में एक 'प्रतिभागी' की भूमिका के लिए। भारत अब 'शिकायतकर्ता' नहीं रह सकता, और निश्चित रूप से 'याचिकाकर्ता' भी नहीं। सिंह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि यह देश में,

दुनिया के बारे में और विदेश में, भारत के बारे में “मानसिकता में बदलाव” का आह्वान करता है। सिंह की परियोजना भारत को अपने पारंपरिक उपनिवेश विरोधी “तीसरे विश्ववाद” से “समावेशी वैश्वीकरण” के उपनिवेशवाद के बाद की धारणा में स्थानांतरित करना था।

‘पीड़ित’ से ‘प्रतिभागी’ बनने के इस विकास में एक महत्वपूर्ण कदम “प्रमुख शक्तियों” के साथ भारत के संबंधों का एक नया दृष्टिकोण होगा। डॉ सिंह का मानना था कि चीन की तरह भारत को भी महाशक्तियों के प्रति पीड़ित मानसिकता अपनाने के बजाय अधिक आत्मविश्वास के साथ उनसे जुड़ना सीखना चाहिए। सोच में इस बदलाव को ट्रिगर करने के लिए ही उन्होंने भारत के औपनिवेशिक अनुभव के अधिक ‘संतुलित’ और ‘सूक्ष्म’ दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने का फैसला किया। उनका कहना था कि भारत को इतिहास से सीखना चाहिए लेकिन इतिहास का कैदी नहीं बनना चाहिए। उदाहरण के लिए, इसे ब्रिटेन जैसे देश से निपटने में एक समान के रूप में सक्षम होना चाहिए, जो अब “वैश्विक शक्ति” या ‘शाही शक्ति’ नहीं है। सिंह का मानना था कि यह गांधीजी और नेहरू चाहते थे कि ‘स्वतंत्र’ भारत उत्तर-औपनिवेशिक ब्रिटेन से संबंधित हो। यह वह विचार था जिसे सिंह ने 8 जुलाई 2005 को अपने प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के भाषण में विस्तार से बताया। साम्राज्य के सामने घुटने टेकने के विपरीत, यह आत्मविश्वास का एक साहसिक बयान था, जिसमें भारतीयों से पूर्व शासक की आंखों में देखने का आग्रह किया गया था। सिंह के विश्व दृष्टिकोण की जड़ें उनके डॉक्टरेट शोध कार्य से आती हैं, जिसने भारत के आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार के महत्व को मान्यता दी। हालाँकि, 1980 के दशक में और 1990 के दशक की शुरुआत में ही भारत ने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण और राष्ट्रीय विकास में व्यापार की भूमिका पर अपना दृ

ष्टिकोण बदल दिया। एक वित्त मंत्री के रूप में और बाद में, प्रधान मंत्री के रूप में, सिंह ने व्यापार के रणनीतिक आयाम की पूरी तरह से सराहना की। व्यापार केवल तुलनात्मक लाभ और बाजार पहुंच के बारे में नहीं है यह “अंतर-निर्भरता के जाल” बनाता है। कई साल पहले, व्यापार अर्थशास्त्री आर एन कूपर ने “व्यापार नीति विदेश नीति है” (विदेश नीति, 1972) शीर्षक से एक निबंध लिखा था। हालाँकि, व्यापार व्यवस्था में क्षेत्रवाद के विकास के साथ, यह और भी स्पष्ट हो गया था कि व्यापार अन्योन्याश्रित संबंधों का निर्माण करता है जो राजनीतिक संबंधों को आकार देते हैं। यह युद्ध के बाद के पश्चिमी यूरोप का अनुभव था और एशिया को भी इसी का लाभ मिल रहा था। भारत को प्रमुख शक्तियों और पड़ोसियों के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार व्यवस्था में भी प्रवेश करना चाहिए।“

व्यापार के प्रति भारत के दृष्टिकोण में सबसे नाटकीय बदलाव उरुग्वे दौर की बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के दौरान आया। भारत 1980 के दशक के उत्तरार्ध में व्यापार पर अपनी पारंपरिक मुद्रा को अपनाने और व्यापार उदारीकरण के एक नए दौर के आह्वान का विरोध करने के दौर में चला गया। 1991 के आर्थिक संकट ने सरकार को अपना रुख बदलने और कई विशेषज्ञ निकायों की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए मात्रात्मक प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए मजबूर किया। आयात और टैरिफ कम करने के परिणामस्वरूप भारत ने उरुग्वे दौर में अपने बातचीत के रुख को बदल दिया और अंततः विश्व व्यापार संगठन के निर्माण के लिए हस्ताक्षरकर्ता बन गया। ‘समावेशी वैश्वीकरण’: दक्षिण आयोग में अपनी सोच से उत्पन्न, सिंह विकास सहयोग की एक महत्वपूर्ण अवधारणा के साथ आगे आए, जिसे उन्होंने “समावेशी वैश्वीकरण” करार दिया। उन्होंने पहली बार अप्रैल 2005 में बांडुंग शिखर सम्मेलन की 60 वीं

वर्षगांठ के अवसर पर एशियाई और अफ्रीकी देशों के प्रमुखों के ऐतिहासिक जकार्ता शिखर सम्मेलन में अपने हस्तक्षेप के दौरान इस अवधारणा का अनावरण किया, और कैम्बिज विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम में अपने विशेष दीक्षांत समारोह में इसे विकसित किया। अक्टूबर 2006, जकार्ता शिखर सम्मेलन में, सिंह ने उपनिवेशवाद के बाद की ‘पुरानी बयानबाजी’ से परहेज किया और वैश्वीकरण की एक अधिक समावेशी धारणा को सामने रखा।

इस सम्मेलन में डॉ सिंह ने कहा

“ हमारा अभूतपूर्व संपर्क तकनीक की दुनिया में हैं। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्रांतियों के लिए धन्यवाद, दूरी ने अपना पुराना अर्थ खो दिया है। बांडुंग 1955 के पचास वर्षों बाद, हम एक छोटे और अधिक एकीकृत प्रवासन में मिलते हैं और अधिक खुली अर्थव्यवस्थाएं बहु-सांस्कृतिक दुनिया बना रही हैं। समाज वैश्वीकरण सूचना और मुक्त प्रतिस्पर्धा के अवसरों की तत्काल उपलब्धता को सक्षम बनाता रहा है ... यह संयोग नहीं है कि बढ़ता हुआ खुलापन, लोकतंत्र और सामाजिक जागरूकता वैश्वीकरण की प्रक्रिया के दौर को ही बढ़ावा दे रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हालिया प्रगति हमें पुरानी समस्याओं जैसे गरीबी, अज्ञानता की समस्याएं और बीमारी से निपटने के लिए अद्वितीय साधन प्रदान करती है। ठीक से प्रबंधित, वैश्वीकरण एक पीढ़ी की अवधि में ही मानव स्थिति में एक महत्वपूर्ण सुधार को प्रभावित कर सकता है। यहां तक कि सितंबर 2006 में हवाना में एनएएम शिखर सम्मेलन में, डॉ सिंह ने ‘वैश्वीकरण में’ के बारे में बात की और कहा कि वे एनएएम को वैश्विक विभाजन के बीच एक “पुल” के रूप में देखते हैं और “चरम की अस्वीकृति” के रूप में भी। उन्होंने चावेज और अहमदीनिजाद के चरमपंथी “अनन्य” दृष्टिकोणों को जानबूझकर अपने “समावेशी” दृष्टिकोण से

अलग किया। सिंह ने एनएएम को बताया, “हम एक तेजी से अन्योन्याश्रित दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। आगे की चुनौती राष्ट्रों की इस अन्योन्याश्रितता के एक संतुलित और न्यायसंगत प्रबंधन को बढ़ावा देना है। जैसे-जैसे वैश्वीकरण आगे बढ़ रहा है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सीमाएं कम से कम प्रासंगिक होती जा रही हैं। राष्ट्रों के रूप में हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वे उत्तरोत्तर कम होती जा रही हैं और स्थितियाँ विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय और स्वायत्त समाधानों के लिए उत्तरदायी होती जा रही हैं। पर्यावरणीय क्षरण और जलवायु परिवर्तन कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं मानते हैं। एचआईवीधर्डस, मलेरिया, टीबी या एवियन फ्लू जैसी महामारियों को केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ही नियंत्रित या दूर किया जा सकता है। कहीं भी आतंकवाद हर जगह शांति के लिए खतरा है। हमारी समस्याएं वैश्विक हैं, तो हमारे समाधान भी वैश्विक ही होने चाहिए”

ग्रंथ सूची

1. बजट भाषण, फरवरी 28, 1997
2. मनमोहन सिंह जी के चयनित भाषणों से, वॉल्यूम 1, पब्लिकेशंस डिविजन, भारतीय सरकार, 2005
3. लोकसभा में मनमोहन सिंह, 10 मार्च 2005 www-pmindi-nic-in/speeches.htm
4. सी. राजमोहन, “रीथिंकिंग इंडियाज ग्रैंड स्ट्रेटेजी”, एन. एस. सिसोदिया और सी उदय भास्कर (संकलन) इमर्न्यूज़ इंडिया, डिल्ही एंड शिकागो, 2005
5. संजय बारू को दिया मनमोहन सिंह जी का साक्षात्कार 30वीं सालगिरह, विशेष संस्करण, द इकॉनॉमिक टाइम्स 15 मार्च 1991

6. इंस्टीट्यूट आफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, नवंबर 11, 2005 www.pmindia-nic-in/speeches-htm चयनित भाषण वॉल्यूम 2
7. मनमोहन सिंह, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी, स्पेशल कन्वोकेशन भाषण जुलाई 8, 2005
8. इंडियन एक्सप्रेस मई 8, 2006
9. संजय बारु, लेख, "द इकोनॉमिक कॉस्मिकवेंसेज ऑफ कॉनफिलक्ट फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान", बारु 2006 में
10. मनमोहन सिंह द्वारा दिए विभिन्न भाषणों से, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तथा अन्य राष्ट्रीय स्तर पर